भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2672
बुधवार, 11 दिसम्बर, 2019/20 अग्रहायण, 1941 (शक)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी/रोजगार

2672. श्री रंजिब बिस्वालः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कितनी नौकरियों का सृजन किया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय या अन्य के माध्यमों से बेरोजगार युवाओं को प्रदान की गई नौकरियों/रोजगार की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार ने देश में बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरियों का सृजन करने के लिए क्या-क्या अन्य कदम उठाए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) तथा श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए रोजगार-बेरोजगारी संबंधी वार्षिक सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैः

बेरोजगारी दर (%) में	
सर्वेक्षण	अखिल-भारत
2017-18 (पीएलएफएस)	6.0%
2015-16 (श्रम ब्यूरो)	3.7%
2013-14 (श्रम ब्यूरो)	3.4%

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया हैं।

पीएलएफएस के परिणाम के अनुसार, 2017-18 के दौरान अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात 46.8% था और श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षणों के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात 2013-14 तथा 2015-16 के दौरान क्रमशः 53.7% एवं 50.5% था।

इसके अतिरिक्त, देश में पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षणों में प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य रूप से कार्यशील व्यक्तियों का सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित प्रतिशत वितरण नीचे दिया गया हैः

प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य रूप से कार्यशील व्यक्ति			
क्षेत्र	2013-14 (श्रम ब्यूरो)	2015-16 (श्रम ब्यूरो)	2017-18 (पीएलएफएस)
प्राथमिक	48.3%	47.3%	44.1%
द्वितीयक	22.4%	21.9%	24.8%
तृतीयक	29.3%	30.8%	31.1%

(टिप्पणीः पीएलएफएस एवं श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण की कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श का चयन अलग-अलग है।)

(ग): राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की उपलब्ध सीमा तक संख्या अनुबंध-।। में दी गई है।

(घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय देश भर में चार वर्षों अर्थात् 2016-2020 तक 12,000 करोड़ परिव्यय से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) एवं पूर्व सीखने को मान्यता (आरपीएल) के तहत एक करोड़ व्यक्तियों को कौशल प्रदान कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 2016-20 नामक एक फ्लैगशीप योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 11.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2672 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा के अनुसार बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)		
		श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण		एनएसएस के सर्वेक्षण (पीएलएफएस)
		2013-14	2015-16	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	2.9	3.5	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	3.9	5.8
3.	असम	2.9	4.0	7.9
4.	बिहार	5.6	4.4	7.0
5.	छत्तीसगढ़	2.1	1.2	3.3
6.	दिल्ली	4.4	3.1	9.4
7.	गोवा	9.6	9.0	13.9
8.	गुजरात	0.8	0.6	4.8
9.	हरियाणा	2.9	3.3	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	1.8	10.2	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	8.2	6.6	5.4
12.	झारखंड	1.8	2.2	7.5
13.	कर्नाटक	1.7	1.4	4.8
14.	केरल	9.3	10.6	11.4
15.	मध्य प्रदेश	2.3	3.0	4.3
16.	महाराष्ट्र	2.2	1.5	4.8
17.	मणिपुर	3.4	3.4	11.5
18.	मेघालय	2.6	4.0	1.6
19.	मिजोरम	2.0	1.5	10.1
20.	नागालैंड	6.7	5.6	21.4
21.	ओडिशा	4.3	3.8	7.1
22.	पंजाब	5.4	5.8	7.7
23.	राजस्थान	3.1	2.5	5.0
24.	सिक्किम	7.1	8.9	3.5
25.	तमिलनाडु	3.3	3.8	7.5
26.	तेलंगाना	3.1	2.7	7.6
27.	त्रिपुरा	6.2	10.0	6.8
28.	उत्तराखंड	5.5	6.1	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	4.0	5.8	6.2
30.	पश्चिम बंगाल	4.2	3.6	4.6
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13.0	12.0	15.8
32.	चंडीगढ़	2.8	3.4	9.0
33.	दादर और नगर हवेली	4.6	2.7	0.4
34.	दमन और दीव	6.6	0.3	3.1
35.	लक्षद्वीप	10.5	4.3	21.3
36.	पुडुचेरी	8.8	4.8	10.3
	अखिल भारत	**3.4**	**3.7**	**6.0**

स्रोत: 1. वार्षिक रिपोर्ट, पीएलएफएस, 2017-18, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

2. रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो।

टिप्पणी: पीएलएफएस और श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण में सर्वेक्षण कार्य-पद्धति तथा प्रतिदर्श चयन अलग-अलग है।

अनुबंध -II

राज्य सभा के दिनांक 11.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2672 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों का उपलब्ध सीमा तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	नियोजन (हजार में)		
		2015	**2016**	**2017***
1	आंध्र प्रदेश	0.20	0.50	0.16
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.85	0.60	0.55
4	बिहार	1.10	1.90	0.00
5	छत्तीसगढ़	3.18	0.20	0.25
6	दिल्ली	0.19	0.00	0.00
7	गोवा	2.91	1.10	0.00
8	गुजरात	336.67	330.10	274.43
9	हरियाणा	0.28	0.40	0.05
10	हिमाचल प्रदेश	1.11	1.50	0.25
11	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.20	0.97
12	झारखंड	2.95	2.50	2.78
13	कर्नाटक	0.79	0.70	0.27
14	केरल	8.22	11.30	6.15
15	मध्य प्रदेश	0.11	0.10	0.00
16	महाराष्ट्र	22.88	37.60	1.28
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
18	मेघालय	0.15	0.00	0.01
19	मिजोरम	0.01	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	1.25	3.80	3.76
22	पंजाब	1.71	2.60	1.58
23	राजस्थान	0.39	0.10	0.10
24	सिक्किम#	-	-	-
25	तमिलनाडु	7.73	6.20	1.24
26	तेलंगाना	0.50	0.50	0.06
27	त्रिपुरा	0.38	0.20	0.01
28	उत्तराखंड	0.22	0.30	0.05
29	उत्तर प्रदेश	0.41	1.50	0.08
30	पश्चिम बंगाल	0.47	1.20	0.00
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.11	0.40	0.00
32	चंडीगढ़	0.08	0.20	0.08
33	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
34	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
36	पुडुचेरी	0.09	0.10	0.00
	योग@	**394.99**	**405.50**	**294.12**

स्रोत: रोजगार सांख्यिकी कार्यालय, रोजगार महानिदेशालय

टिप्पणी: # इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है;

@ हो सकता है कि पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं; *अगस्त, 2017 तक (अनंतिम)